पदोन्नति में पेंचीदगी, गंभीरता से हो रहा विचार, जल्द निकलेगा समाधानः शिवराज

शहर प्रतिनिधि, भोपाल। पदोन्नति में पेंचीदगी है। सरकार पदोन्नति शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जल्द ही सभी की सहमति से इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के नवीन कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर कही। पौने पांच साल से अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगी रोक पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा फार्मूला तैयार कर रहे हैं, जिसमें किसी को कोई दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा कहा नहीं जा सकता है। मुझे पीड़ा होती है कि कर्मचारी बगैर पदोन्नति सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में मुझे सलाह दी थी कि कर्मचारियों का वेतन 60, 70, 80 फीसदी कर दो, पर मैंने इंकार कर दिया। महंगाई भत्ता नहीं दे पाए हैं। जैसे ही आर्थिक स्थिति संभलेगी। एक-एक पैसा देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी, कर्मचारी है। विभाग और वर्गों में न बंटें। कर्मचारी इधर-उधर के हो जाएं तो स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझमें मुख्यमंत्री का अहंकार नहीं है। मैं फालतू की राजनीति नहीं करता। मैं सीएम के नाते काम कर रहा हूं और आप कर्मचारी के नाते। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सतर्कता केंद्र का भी लोकार्पण किया। जिसमें कर्मचारियों की जिम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। उक्त केंद्र में कर्मचारियों के लिए सप्ताह में एक-एक दिन अलग-अलग पैथी के डाक्टर मौजूद रहेंगे।

Badri Gautam

इस बार मूड अलग है और तेवर भी : मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में सभी के सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि इस बार मूड भी अलग है और तेवर भी। माफियाओं का सफाया करके रहेंगे। दादा, पहलवान, मसल्स पॉवर और धनी पॉवर सब छिपे फिर रहे हैं। मैंने कहा कि इन्हें पूरी तरह से तबाह करो। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सिर्फ एफआइआर होती थी। उससे क्या होता है, मैंने कहा है कि उनकी संपत्ति तोड़कर और राजसात करके वसूल करो। अभी 600 और 200 करोड़ रुपये बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोचा था पांच साल धरना-आंदोलन करेंगे। सवा साल में ही लौट आए।

भगवान करे-कोरोना महराज समाप्त हो जाएं : मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान करे कोरोना महराज समाप्त हो जाएं। सदी में ऐसी महामारी आती है, जो अब समाप्त होने की ओर है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे स्थिति सुधरेगी, कर्मचारियों की मांगें चर्चा करके पूरी करेंगे।

स्मार्ट सिटी में कर्मचारियों के लिए 400 मकान दिए जाए : संघ के अध्यक्ष इंजी. सुधीर नायक ने संबोधित करते हुए कर्मचारियों की मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि सरकार को पदोन्नति का हल जल्द निकालना चाहिए। उन्होंने समान पदों के लिए समान नियम, स्मार्ट सिटी में कर्मचारियों के लिए 400 मकान आरक्षित करने सहित कई मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखीं।

सीएम ने कहा-पदोन्नति मामले में निकालेंगे सर्वसम्मत हल

शिवराज ने जताई चिंता, कहा- वर्गों में न बंटें कर्मचारी

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। पौने पांच साल से अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगी रोक पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार पदोन्नति शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसमें पेचीदगी है, पर सभी की सहमति से जल्द इसका समाधान करेंगे। ऐसा फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, जिसमें किसी को दिक्कत न हो। जरूरत पड़ी तो विचार-विमर्श करने बैठेंगे।

चौहान गुरुवार को मंत्रालय के पुराने भवन में मंत्रालयीन कर्मचारी संघ को आवंटित कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि फैसला कब आएगा कहा नहीं जा सकता है। मुझे पीड़ा होती है कि कर्मचारी बगैर पदोन्नति सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व विधायक शिव चौबे, कर्मचारी नेता सुधीर नायक, राजकुमार पटेल, आलोक वर्मा, मनोज वाथम, डीएस मरकाम, सलीम खान, आशीष सोनी, रचना बिलगैंया, आनंद भट्ट, सतीश शर्मा और हरिशरण द्विवेदी सहित अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में सभी के सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि इस बार मूड भी अलग है और तेवर भी। माफियाओं का सफाया करके रहेंगे। दादा, पहलवान, मसल्स पॉवर और धनी पॉवर सब छिपे फिर रहे हैं। मैंने कहा कि इन्हें पूरी तरह से तबाह करो। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सिर्फ एफआइआर होती थी। अब उनकी संपत्ति तोड़कर और राजसात करके वसूल करेंगे। अभी 600 और 200 करोड़ रुपये बरामद किए हैं। सोचा था पांच साल धरना-आंदोलन करेंगे। सवा साल में ही लौट आए। विपरीत परिस्थितियों में मुझे सलाह दी थी कि कर्मचारियों का वेतन 60, 70, 80 फीसद कर दो, पर मैंने इंकार कर दिया। महंगाई भत्ता नहीं दे पाए हैं। जैसे ही स्थिति संभलेगी एक-एक पैसा देंगे।

Badri Gautam

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। ●जनसंपर्क

वर्गों में न बंटें कर्मचारी : मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी विभाग और वर्गों ने न बंटें। वे इधर-उधर के हो जाएं तो स्थिति ठीक नहीं है। मुझमें मुख्यमंत्री का अहंकार नहीं है। मैं फालतू की राजनीति नहीं करता।

सीएम ने मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के नववर्ष मिलन में दिया भरोसा

कर्मचारियों की पदोन्नति का शीघ्र ही सर्वसम्मत समाधान निकालेंगे

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9425493055

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विगत पांच साल से सरकारी कर्मचारियों की ठप पड़ी पदोन्नति फिर से शुरू करने का सर्वसम्मत समाधान निकाला जाएगा। कोरोना महामारी के कारण बिगड़ी अर्थव्यस्था अब सुधरने लगी है। ऐसे में कर्मचारियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि और स्वास्थ्य बीमा लाभ के साथ में तीन उच्चतर वेतनमान सहित सभी जायज मांगें भी पूरी कर दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के नववर्ष मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर शिव चौबे, एसीएस विनोद कुमार सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री का संघ द्वारा अभिनंदन भी किया गया। इसमें अध्यक्ष सुधीर नायक, कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार पटेल, शिव चौबे, आलोक वर्मा, सलीम खान, ठाकुरदास प्रजापति, आशीष सोनी, यशवंत ढोणे, मतीन खान, संतोष बड़ोदिया, मनोज बाथम, राजमणि पटेल, गणेश बाथम, आनंद भट, हरीश बाथम, देव सिंह मरकाम, मनोहर छतवानी, हरिशरण द्विवेदी, यज्ञसेन वर्मा, रामबाई, सरस्वती बाई, रचना बिलगैयां, सतीश शर्मा, संतशरण सेंगर, राजेन्द्र तिवारी, संतोष हरगोविंद लोधी, अमरजीत पटेल, रमेश मिश्रा मौजूद रहे।

Badri Gautam

मंत्रालय में नववर्ष मिलन समारोह में मुख्यमंत्री को कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मांगों का ज्ञापन सौंपा।

नववर्ष मिलन समारोह में मौजूद महिला-पुरुष कर्मचारी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश को कोरोना की भयावहता से बचाया

मांत्रालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि कोरोना काल में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। उन्होंने दिन-रात काम करते हुए प्रदेश को कोरोना की भयावहता से बचाया है। जब प्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा, तो मुख्यमंत्री के पहले और बाद के काल की तुलना होगी।

स्वास्थ्य सतर्कता केंद्र का शुभारंभ

सीएम ने कर्मचारी संघ के स्वास्थ्य सतर्कता केंद्र का शुभारंभ किया। इसमें ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, वेपराइजर, बीपी मशीन, थर्मल स्कैनर रखे हैं।

दसवीं और बारहवीं की लेट शुरू होगी परीक्षा आनलाइन आएंगे नंबर, जल्द मिलेगा रिजल्ट

परीक्षा पैटर्न के बाद अब मूल्यांकन पद्धति में मंडल कर रहा बदलाव

शहर प्रतिनिधि, भोपाल

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं-बारहवीं परीक्षा दो माह की देरी तीस अप्रैल से शुरू होगी। हालांकि इस बार मंडल रिजल्ट जल्दी देने की तैयारी कर रहा है। विद्यार्थियों की कॉपियों का जिलों में ही मूल्यांकन कर आनलाइन नंबर बुलवाए जाएंगे। विद्यार्थियों के नंबर भी हर प्रश्न के उत्तर के अलग-अलग बुलवाए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा पैटर्न के बाद अब मूल्यांकन पद्धति में भी बदलाव करने जा रहा है।

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल दसवीं-बारहवीं बोर्ड परीक्षा तीस अप्रैल से शुरू हो रही है। परीक्षा पंद्रह मई तक चलेगी। दूसरी परीक्षा एक जुलाई से 15 जुलाई तक होगी। दो माह की देरी से

परीक्षा होने के कारण मंडल ने मूल्यांकन पद्धति में बदलाव कर रहा है। इसके तहत जिले में ही कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। जिससे एक विषय का पेपर खत्म होने के बाद उसके दूसरे दिन उस विषय की कॉपियां जांचनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही एक-एक विषय के एक-एक प्रश्न का रिजल्ट समन्वयक केंद्रों से बोर्ड को ऑनलाइन भेजे जाएंगे, जिससे विषयवार रिजल्ट भी मंडल की वेबसाइट पर प्रदर्शित होने लगेंगे। साथ ही विषयवार कॉपियों का परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अब बोर्ड परीक्षा में कम नंबर आने पर विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का रि-वैल्यूशएन भी करा सकेंगे। अभी तक बोर्ड के विद्यार्थी सिर्फ रि-टोटलिंग के लिए आवेदन कर पाते थे, लेकिन अब दोनों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

Badri Gautam

फरवरी में होगी प्री-बोर्ड परीक्षा

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की मुख्य परीक्षा के पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्री-बोर्ड परीक्षा होगी। लोक शिक्षण द्वारा आयोजित यह परीक्षा आनलाइन कराने पर विचार कर रहा है। हालांकि इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

निजी स्कूलों में बनेंगे अधिक परीक्षा केंद्र

माशिमं द्वारा परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में साफ कहा है कि परीक्षा केंद्रों लिए ऐसे स्कूलों का चयन किया जाए, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, फोटो कॉपी मशीन उपलब्ध हो या किराए पर आसानी से ली जा सके। साथ ही परीक्षा केंद्रों के चयन में स्कूलों में उपलब्ध अधोसंचरना, संसाधन एवं सुविधाओं के आधार पर किया जाए। साथ ही स्कूलों की दूरी शहरी क्षेत्र में पांच किमी एवं ग्रामीण क्षेत्र में दस किमी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। परीक्षा केंद्र के लिए ऐसे स्कूलों का चयन किया जाए, जिसमें परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था के लिए फर्नीचर, पेयजल, प्रसाधन व सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। ऐसे कोई भी स्कूल परीक्षा के लिए प्रस्तावित नहीं किया जाए, जहां टेंट या शामियाना में, टाटपट्टी या जमीन पर परीक्षार्थियों को को परीक्षा देने की स्थिति उत्पन्न हो।

अब मप्र बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जिले में ही जांची जाएंगी, रिजल्ट जल्दी होगा घोषित

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) सत्र 2020-21 से बोर्ड परीक्षा पैटर्न के साथ-साथ कॉपी जांचने और मूल्यांकन में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। भले ही इस बार बोर्ड परीक्षा दो माह की देरी से अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू की जा रही हैं, लेकिन माशिमं रिजल्ट जल्द घोषित करने की तैयारी में है। इसके लिए इस बार जिले में ही कॉपियां जांची जाएंगी। एक विषय का पेपर होने के बाद दूसरे दिन ही उस विषय की कॉपियां जांचने का काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही एक-एक विषय का रिजल्ट समन्वयक केंद्रों से बोर्ड को ऑनलाइन भेजा जाएगा, जिससे विषयवार रिजल्ट भी माशिमं की वेबसाइट पर प्रदर्शित होने लगेगे। साथ ही विषयवार कॉपियों का परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड

कर दिया जाएगा। इसके अलावा अब बोर्ड परीक्षा में कम नंबर आने पर विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन भी करा सकेंगे। अभी तक बोर्ड के विद्यार्थी सिर्फ पुनर्गणना के लिए आवेदन कर पाते थे, लेकिन अब दोनों के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिन विद्यार्थियों को बोर्ड से मिले अंकों पर शक है तो वे हर विषय का पुनर्मूल्यांकन करा सकेंगे। बता दें कि इस बार बोर्ड दो परीक्षा ले रहा है। 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक चलेगी। वहीं, दूसरी परीक्षा एक से 15 जुलाई तक होगी।

पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन होगा आवेदन : बोर्ड ने पुनर्मूल्यांकन में यह व्यवस्था की है कि ऑनलाइन आवेदन होंगे। पहले आठ दिन कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कराने पर 100 रुपये फीस देनी होगी। उसके आठ दिन बाद 50 रुपये लगेंगे। उसके बाद कोई शुल्क नहीं लगेगा।

इस साल से 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में जल्द ही प्रक्रिया बनाकर दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर भी नए बदलाव की तैयारी है।

-बलवंत वर्मा, परीक्षा नियंत्रक, माशिमं

Badri Gautam

मध्यप्रदेश में योजना और विभागों का नाम बदलना बना ट्रेंड, व्यापमं से हुई थी शुरूआत

अब लोक शिक्षण संचालनालय का भी नाम बदलेगी सरकार

भास्कर ब्यूरो | भोपाल

सरकार में विभागों और योजनाओं का नाम बदलना एक ट्रेण्ड बन गया है। व्यापमं की बदनाम छवि सुधारने के लिए सरकार ने नाम बदल कर पीईबी रख दिया था, लेकिन मप्र में योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं। इसी तरह विभागों के नाम में भी बदले जा रहे है। अब राज्य सरकार लोक शिक्षण संचालनालय का नाम बदलने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव सीएम के समक्ष रखा जाएगा। बताया जा रहा है पिछले दिनों स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विभागीय बैठक के दौरान प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। लेकिन विभाग को नया नाम नहीं सुझाया है। नाम परिवर्तन में जुटे विभाग के उच्चाधिकारी नया नाम तय कर प्रस्ताव सीएम के समक्ष रहेंगे।

व्यापमं का 2015 में बदला था नाम

व्यापमं घोटाले से हुई बदनामी से परेशान मप्र सरकार ने अगस्त 2015 में व्यापमं नाम को ही दफन कर दिया था। व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रखा गया। व्यापमं के नाम का अंग्रेजीकरण ठीक उस समय हुआ है जब विश्व हिंदी सम्मेलन के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में हिंदी के लिए मुहिम शुरू की थी।

Badri Gautam

नाथ सरकार ने बदला था शिवराज की इन योजनाओं का नाम

सियासी घमासान में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने जुलाई, 2019 में शिवराज सरकार के समय शुरू की गईं लगभग आधा दर्जन योजनाओं का या तो बंद कर दिया था या इनका नाम बदलकर नए नाम से चलाया जा रहा था।

» **धर्मस्व विभाग :** पिछली सरकार के समय लोगों के लिए शुरू किया गया धर्मस्व विभाग का नाम कमलनाथ सरकार ने बदल कर अध्यात्म विभाग कर दिया था।

» **संबल योजना :** विस चुनाव से ठीक पहले भाजपा सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए संबल योजना शुरू की थी। लोगों में खासी लोकप्रिय शिवराज की इस महत्वाकांक्षी योजना का कमलनाथ सरकार ने नाम बदलकर 'नया सवेरा' कर दिया था।

» **समाधान ऑनलाइन योजना :** कमलनाथ सरकार ने समाधान ऑनलाइन योजना का नाम बदलकर जन अधिकार कर दिया है।

» **इंदिरा गृह ज्योति योजना :** शिवराज सरकार के समय शुरू की गई सरल योजना का नाम बदलकर सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए इंदिरा किसान योजना शुरु की थी।

फिर किसान मित्र बनी योजना

कमलनाथ सरकार ने भर्ती प्रक्रिया के लिए किसान मित्र योजना का नाम बदलकर कृषक बंधु रख दिया था। किसान मित्र और किसान दीदी का पदनाम बदलकर कृषक बंधुओं के पद पर राज्य सरकार नियुक्तियां भी कर रही थी। अब करीब 11 माह बाद शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार द्वारा बदले गये नाम को खारिज करते हुए योजना को पूर्व की तरह ही किसान मित्र के नाम से संबोधित करने की घोषणा की है।

दो बार बदला ट्रायबल का नाम

आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया था। बाद में कमलनाथ सरकार ने तत्कालीन ट्रायबल मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने पूर्व का नाम ही लागू कर दिया। इसी नाम से विभाग को संबोधित किया जाने लगा। अब शिवराज सरकार ने फिर से नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग रख दिया है।

हर सरकारी स्कूल में बनवाए जाएंगे किचन गार्डन

पोषण वाटिकाओं (किचन गार्डन) का नाम होगा माँ की बगिया

भोपाल, (प्रसं)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से हर शासकीय स्कूल में पोषण वाटिका (किचन गार्डन) बनवाए जाएंगे। स्कूलों में जगह न होने पर गांव में अन्य स्थान पर भी पोषण वाटिका बनाई जा सकती है। श्री चौहान ने कहा कि अब पोषण वाटिका का नाम'माँ की बगिया'होगा। स्कूल की स्वच्छता एवं माँ की बगिया के विकास एवं संरक्षण में विद्यार्थियों का पूरा योगदान लिया जाए।मुख्यमंत्री गुरुवार को यहां प्रदेश में निर्मित 2500 किचन शेड और 7100 पोषण वाटिकाओं के लोकार्पण के बाद संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने किया ने 2500 किचन शेड एवं 7100 पोषण वाटिकाओं का लोकार्पण

सीएम ने इनसे किया वर्चुअल संवाद: मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में बालाघाट जिले के ग्राम जंगलटोला की सरपंच श्रीमती गुणवंता बिसेन, ग्वालियर जिले के ग्राम उटीला (मुरार) के शिक्षक पालक संघ के अध्यक्ष देवेन्द्र बघेल तथा गायत्री देवी से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने अच्छा किचन शेड निर्माण के लिए उन्हें बधाई दी।

Badri Gautam

हम तो अपने स्कूल में झाड़ू लगाते थे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पहले बच्चे अपने स्कूल में स्वच्छता तथा स्कूल की तरक्की में अपना पूरा योगदान देते थे। हम तो अपने स्कूल में झाड़ू लगाते थे। स्कूल की स्वच्छता आदि के काम में कोई शर्म नहीं है। विद्यार्थियों को यह काम करना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि भोजन हितभुक अर्थात शरीर के लिए लाभदायी, मितभुक अर्थात सीमित मात्रा में तथा ऋतुभुक अर्थात मौसम के अनुरूप होगा, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्कूल में पोषण वाटिका बनाने का उद्देश्य है कि बच्चों को ताजी व अच्छी सब्जियां मध्यान्ह भोजन के लिए मिल सकें।

मैं सीएम हाउस के किचन गार्डन का नाम भी मां की बगिया रखूंगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान को भोपाल जिले के फंदा की प्राथमिक शाला, सिकंदराबाद की स्व-सहायता समूह की रसोइया श्रीमती सुनीता मारन ने बताया कि उन्होंने स्कूल में बनाई गई पोषण वाटिका का नाम'माँ की बगिया'रखा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपयुक्त नाम है। अब प्रदेश की सभी पोषण वाटिकाओं को'माँ की बगिया'कहा जाएगा। मैं सीएम हाऊस के किचन गार्डन का नाम भी माँ की बगिया रखूंगा।

किताब खोलकर दी दक्षता परीक्षा फिर भी पास नहीं हुए

मैथ में सर्वाधिक डिसक्वालिफाई आर्ट में भी फेल हुए शिक्षक

दो महीने तक फेल शिक्षकों की होगी ट्रेनिंग, फिर देनी होगी परीक्षा

जागरण, रीवा

दक्षता परीक्षा में रीवा के शिक्षक भी फेल हुए। 50 अंक क्वालिफाई के लिए निर्धारित थे। हद तो यह है कि दक्षता परीक्षा मे करीब 30 फीसदी शिक्षक किताब खोल कर भी पास नहीं हो पाए। गणित में सर्वाधिक फेल हुए। अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और आर्ट में भी इनकी संख्या सर्वाधिक ही रही। इन फेल शिक्षकों को अब दो महीने पढ़ाई करने के बाद फिर परीक्षा देनी होगी।

ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 40 फीसदी कम अंक लाने वाले शिक्षकों के लिए दक्षता मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया था। 3 और 4 जनवरी को परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में 1102 शिक्षक शामिल हुए। 3 जनवरी को हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के शिक्षकों की परीक्षा आयोजित की गई। इसमें 4 शिक्षक अनुपस्थित रहे। इसी तरह 4 जनवरी को कैचमेंट की माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की परीक्षा आयोजित हुई। इसमें करीब 39 शिक्षक नदारद रहे। इन शिक्षकों को विभाग ने नोटिस जारी कर इतिश्री कर लिया। वहीं जिन्होंने परीक्षा दी उनके परीक्षा परिणाम तैयार कर 4 जनवरी की रात ही भोपाल भेज दिए गए। परीक्षा में अनुपस्थिति शिक्षकों को छोड़ दिया जाए तो

फाइल फोटो

Badri Gautam

1059 ने परीक्षा दी। इसमें से करीब 30 फीसदी फेल हो गए। इनके रिकार्ड भोपाल पहुंच गए हैं। इन शिक्षकों को अब स्कूल शिक्षा विभाग 2 महीने पढ़ाएगा। विषय विशेषज्ञ की ट्रेनिंग चलेगी। इसके बाद फिर परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में पास नहीं हुए तो कार्रवाई तय है।

किताब खोलकर भी नहीं लिख पाए

शिक्षक दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में शिक्षकों को विषय से संबंधित किताबें खोल कर प्रश्नों के जवाब देना था। वह भी शिक्षक नहीं कर पाए। सबसे अधिक गणित के शिक्षक इस परीक्षा में डिसक्वालिफाई हुए। इसके अलावा आर्ट, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में भी शिक्षक फेल हुए हैं।

3 जुलाई को होगी जेईई एडवांस्ड परीक्षा 75 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता खत्म

एजेंसी ● नई दिल्ली

editor@peoplessamachar.co.in

Badri Gautam

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2021 की तारीख का ऐलान कर दिया। इस वर्ष जेईई एडवांस्ड परीक्षा का आयोजन 3 जुलाई 2021 को होगा। साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रवेश के लिए 12वीं में 75% अंकों की अनिवार्यता संबंधी शर्त को भी हटा

लिया गया है। पिछले वर्ष भी कोरोना के चलते 75 फीसदी अंकों की बाध्यता से छूट दी गई थी।

शिक्षा मंत्री ने कहा, इस वर्ष इस परीक्षा का आयोजन आईआईटी खड़गपुर द्वारा किया जाएगा। वेबिनार के जरिए शिक्षा मंत्री ने कहा, जेईई मेन 2021 की तारीखों के ऐलान के बाद से ही विद्यार्थी लगातार जेईई एडवांस्ड के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे। सरकार ने जेईई मेन 2020 पास करने वाले उन विद्यार्थियों को सीधे जेईई एडवांस्ड 2021 में बैठने की अनुमति दी है, जो कोरोना महामारी के चलते जेईई एडवांस्ड 2020 में नहीं बैठ सके थे। इन छात्रों को जेईई मेन 2021 देने की जरूरत नहीं है। इन्हें सीधा जेईई एडवांस्ड 2021 में बैठने का मौका मिलेगा। ऐसे में इस बार जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक होगी।

जेईई एडवांस्ड की परीक्षा में हुए बदलाव

इस बार 12वीं की परीक्षा में 75 फीसदी अंक लाना जरूरी नहीं

नई दिल्ली | एजेंसी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को आईआईटी में दाखिले के लिए पात्रता मानदंड और जेई एडवांस परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल ने कहा कि जेईई एडवांस 2021 की परीक्षा 03 जुलाई, 2021 को आयोजित की जाएगी। इस बार परीक्षा का आयोजन आईआईटी, खड़गपुर द्वारा किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कक्षा 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 75% कुल अंक लाने के पात्रता मानदंड इस वर्ष लागू नहीं होंगे।

Badri Gautam

पात्रता की रहेगी छूट

वहीं, नियम के अनुसार, छात्रों को एडवांस्ड परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए हर साल जेईई मेन पास करना होता है, लेकिन महामारी के कारण, जिन छात्रों ने जेईई मेन 2020 को क्लीयर किया था, लेकिन जेईई एडवांस्ड 2020 के लिए उपस्थित नहीं हुए थे, उन्हें जेईई एडवांस्ड 2021 में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। यह वन टाइम ऑप्शन दिया जा रहा है। जेईई मेन परीक्षा के अंतिम सत्र के परिणाम घोषित होने के बाद ही जेईई एडवांस का आयोजन होगा।

एलान... इस साल तीन जुलाई को होगी जेईई एडवांस

नई दिल्ली (ब्यूरो)। आइआइटी सहित देश के चुनिदा शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली अंतिम परीक्षा जेईई एडवांस की तारीखों का भी एलान हो गया है। इस साल यह परीक्षा तीन जुलाई को होगी। इसके साथ ही छात्रों को एक बड़ी राहत देते हुए आइआइटी में प्रवेश के लिए बारहवीं में 75 फीसद अंकों की पात्रता से भी राहत दी गई है। यानी आइआइटी में प्रवेश के लिए बारहवीं अंकों का कोई बंधन नहीं रहेगा। इसकी जगह उन्हें सिर्फ फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ के साथ बारहवीं पास होना जरूरी होगा।

तैयारी को छह माह

- जेईई मेंस और बोर्ड परीक्षाओं के चलते जुलाई में कराने का फैसला
- आइआइटी में प्रवेश के लिए 12वीं में 75% अंकों की पात्रता भी समाप्त

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को ट्विटर के जरिये इसका एलान किया। साथ ही बताया कि इस बार जेईई एडवांस-2021 परीक्षा के आयोजन का जिम्मा आइआइटी खड़गपुर को दिया गया है। जो कोरोना की तय गाइडलाइन को देखते हुए परीक्षाओं का बेहतर बंदोबस्त करेगा।

Badri Gautam

नेहरू, पटेल और आंबेडकर को मिली जगह

एमपी पीएससी ने पुराने सिलेबस को किया अपग्रेड, वर्ल्ड हिस्ट्री को हटाया

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) ने पुराने सिलेबस को अपग्रेड कर नवीन एग्जाम कैलेंडर 2020 में जारी कर दिया है। इसमें दर्जनों बदलाव किए गए हैं।

इन बदलावों में खास बात यह है कि नेहरू, पटेल एवं आंबेडकर को पोलिटिकल थिंकर्स के रूप में जगह मिली है। वहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री को सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके अलावा मानव अधिकार आयोग एवं एससीएसटी आयोग के वृहद दायरे को सीमित किया गया है। आयोग ने सूचना जारी कर बताया कि खान भर्ती 2020 के लिए अब नया सिलेबस लागू होगा। गौरतलब है कि लंबें इंतजार के बाद मप्र लोक सेवा आयोग ने करीब 450 से अधिक पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमे राज्य वन सेवा एवं राज्य सेवा दोनों के पद शामिल हैं। इस बार की भर्ती में आयोग ने एग्जाम कैलेंडर को भी अपग्रेड किया है। इसके साथ ही आईसीटी एवं एआई जैसे पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है।

Badri Gautam

पीईबी: आरक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की तारीख फिर टली

परीक्षा के लिए 8 जनवरी से भरे जाने थे आवेदन फॉर्म

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

मो.नं. 9893231237

Badri Gautam

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) द्वारा 4000 पुलिस आरक्षक पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके लिए आवेदन 8 जनवरी से भरे जाने थे, लेकिन पीईबी ने गुरुवार को आवेदन की तारीख आगे बढ़ा दी है।

यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक एकेएस भदौरिया ने कहा है कि शीघ्र ही आवेदन की अगली तारीख घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि पीईबी द्वारा पूर्व में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदकों को 8 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन भरना था। इससे पहले इसके फॉर्म 24 दिसंबर से भरे जाने थे। परीक्षा नियंत्रक भदौरिया ने बताया कि यह परीक्षा पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग और आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए आयोजित होनी है। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी दो प्रश्न-पत्र के लिए 800 रुपए और एक प्रश्न-पत्र के लिए 600 रुपए फीस के साथ जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 400 व 300 रुपए फीस तय की गई थी। 6 मार्च से दो पालियों में प्रथम पाली सुबह 8.50 से 11 बजे और दूसरी पाली दोपहर 2.50 से 5 बजे तक निर्धारित है।

अभ्यर्थी गर्भवती हुई तो नहीं बन पाएगी सहायक कमांडेंट

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

एजेंसी ● नई दिल्ली

editor@peoplessamachar.co.in

Badri Gautam

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट बनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। यूपीएससी द्वारा इसी साल सहायक कमांडेंट के पदों पर भर्ती की जाएगी। विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की नियमावली में कहा गया है कि यूपीएससी की लिखित परीक्षा में पास हुए सभी उम्मीदवारों का शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। इस दौरान गर्भावस्था को अयोग्यता माना जाएगा। यानी गर्भवती महिला उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरुषों को सौ मीटर की दौड़ 16 सेकेंड में पूरी करनी होगी, महिलाओं को 18 सेकेंड का समय दिया गया है। पुरुष उम्मीदवारों को साढ़े तीन मीटर लंबी कूद लगानी होगी तो वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए यह लंबाई तीन मीटर रखी गई है।

गणतंत्र दिवस 2021 | रक्षा मंत्रालय ने किया आमंत्रित

पहली बार स्कूलों के अलावा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी लेंगे परेड में हिस्सा

नई दिल्ली ■ एजेंसी

इस साल गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राएं भी हिस्सा ले सकते हैं। परेड में अभी तक स्कूली छात्र-छात्राएं ही हिस्सा लेते थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस बार 15 साल से अधिक उम्र के स्टूडेंट ही हिस्सा ले सकेंगे। जानकारी के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय ने देशभर के करीब एक दर्जन विश्वविद्यालयों को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है।

कौन-कौन से विश्वविद्यालय इस साल गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रहे हैं, इसकी जानकारी बहुत जल्द सामने आ जाएगी, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी प्रशासन से जवाब आना अभी बाकी है। यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राएं स्कूली बच्चों की तरह सांस्कृतिक-कार्यक्रम या फिर कोई दूसरी प्रस्तुति पेश कर सकते हैं। इस बार

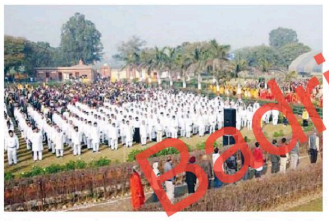

सिर्फ चार स्कूल के छात्र-छात्राएं ही राजपथ पर होने वाली परेड में हिस्सा लेंगे और उन चार स्कूलों की भी कुल तीन टीमें ही अपना कार्यक्रम राजपथ पर दिखा सकेंगी।

इस बार राजपथ पर दिखाई देंगी 32 झांकियां

जानकारी के मुताबिक, इस बार कुल 32 झांकियां राजपथ पर दिखाई देंगी। इनमें से 17 राज्यों की झांकी है और बाकी केंद्रीय मंत्रालयों और सेनाओं (थलसेना, वायुसेना और नौसेना) की झांकी होंगी। इस बार गणतंत्र दिवस परेड भी लालकिले पर खत्म न होकर इंडिया गेट के करीब नेशनल स्टेडियम में ही खत्म हो जाएगी, यानी साढ़े आठ किलोमीटर लंबी परेड को अब मात्र साढ़े तीन किलोमीटर तक ही सीमित कर दिया गया है।

25 हजार से ज्यादा लोग नहीं देख पाएंगे परेड

इस साल परेड देखने वालों की संख्या को भी कम कर दिया गया है। इस साल राजपथ पर 25 हजार से ज्यादा लोग परेड नहीं देख पाएंगे, जबकि हर साल करीब सवा से डेढ़ लाख लोगों तक की भीड़ गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए जुटती थी। इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए 15 साल से कम उम्र के बच्चों को परेड देखने की इजाजत नहीं होगी।

परेड में शामिल होगी बांग्लादेश की सेना की एक टुकड़ी

इस साल गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश सेना की एक टुकड़ी भी भारतीय सैनिकों के साथ कदमताल करती दिखेगी। ये तीसरी बार है जब किसी मित्र देश की सैन्य टुकड़ी राजपथ पर दिखाई पड़ेगी। इससे पहले फ्रांस (2016) और यूएई (2017) के सैनिक भी गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले चुके हैं। खास बात ये है कि भारत ये साल पाकिस्तान पर 1971 के युद्ध में मिली विजय का स्वर्णिम-वर्ष मना रहा है। 1971 के युद्ध के बाद ही पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था।

बांग्लादेश की टुकड़ी में होंगे कुल 122 सैनिक

जानकारी के मुताबिक, बांग्लादेश की टुकड़ी में तीनों सेनाओं के सैनिक शामिल होंगे, यानी बांग्लादेशी थलसेना, वायुसेना और नौसेना। इस टुकड़ी में मिलिट्री बैंड के सदस्यों के साथ-साथ कुल 122 सैनिक होंगे। ये टुकड़ी 12 जनवरी को भारतीय वायुसेना के एक एयरक्राफ्ट से दिल्ली पहुंचेगी और फिर 19 जनवरी तक क्वारंटाइन रहेगी। परेड में हिस्सा लेने के लिए सैन्य टुकड़ी अपनी सेरेमोनियल-राइफल बांग्लादेश से ही लेकर आएगी।

Badri Gautam

30 साल के दैनिक वेतन भोगी दरकिनार , कर रहे सीधी भर्ती

मुख्यमंत्री की भी है घोषणा, जिलों में कमेटी भी हुई गठित, अफसर नियम विरुद्ध कर रहे कार्य

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

वन विभाग में पिछले तीन दशक से दैनिक वेतन भोगियों के रूप में काम करते आ रहे कर्मचारियों के साथ बड़ी चोट की गई है। विभाग में खाली पदों पर इन कर्मचारियों को नियमित के रूप में किया जाना था। आरोप है कि अफसरशाही इन पदों पर सीधी भर्तियां कर रही है। यह प्रक्रिया सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की घोषणा का भी उल्लंघन है। इस मामले में दैनिक वेतन भोगी स्थाई हुए कर्मचारियों ने पत्र लिखकर प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ज से तत्काल भर्ती निरस्त करने की मांग की है।

मंत्री को बताया गया की वनों की सुरक्षा एवं वन्य प्राणियों के रखरखाव में वर्षों से दैनिक वेतन भोगी स्थाई कर्मी अपने प्राणों की आहुति देता रहा है। कई कर्मचारियों की जान भी चली गई, लेकिन विभाग के आला अफसर इस बात से बेखबर है। इतना भी दया भाव नहीं की ऐसे कर्मचारी जो सारी उम्र विभाग में सेवा करते रहे है हैं। जब रिक्त पदों पर नियमित करने की बात हो तो शासन को प्रस्ताव भेजकर सीधी भर्ती भरने में आमादा हो जाते हैं। जबकि अनुभव से बड़ी डिग्री वन्य प्राणियों के देखरेख और रखरखाव के लिए नहीं है। विभाग द्वारा दैनिक वेतन भोगी स्थाई कर्मियों को 2008 में विभागीय मंत्री द्वारा वनरक्षक के पद दैनिक वेतन भोगियों के लिए आरक्षित किए गए जिन पदों पर दैनिक वेतन भोगियों को चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियमित किया था।

Badri Gautam

सरकार को लगाना होगी सीधी भर्ती पर तत्काल रोक

मध्य प्रदेश स्थाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांत अध्यक्ष शारदा सिंह परिहार ने शासन को पत्र लिखकर मांग की है की वनरक्षक के पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए। वन विभाग में स्थाई कर्मी द्वारा वनरक्षक के कार्यों का संपादन वर्षों से किया जा रहा है। उनके अनुभव को प्राथमिकता देते हुए उन्हें वनरक्षक के पद पर नियमित करना होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी यही मंशा थी। इसी मंशा को पूर्ण करने के तारतम्य में शासन द्वारा जिला स्तर पर समिति गठित कर विभाग में पड़े रिक्त पदों को स्थाई कर्मियों से भरने के आदेश प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन नौकरशाही के चलते मुख्यमंत्री की घोषणा का पालन नहीं किया गया केवल आदेश जारी कर इतिश्री कर ली गई है।

मुख्यमंत्री की घोषणा का पालन करना होगा अधिकारियों को : बैरागी

मध्य प्रदेश स्थाई कर्मचारी कल्याण संघ के उपाध्यक्ष घनश्याम बैरागी का कहना है कि अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई है। उसका पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी स्थाई कर्मियों में भारी असंतोष व्याप्त आज प्रदेश का स्थाई कर्मी अनुकंपा नियुक्ति सातवें वेतनमान चिकित्सा सुविधा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है 30 वर्षों की सेवा करने के बाद कोई प्रमोशन प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की गई है। ना समय मान वेतन और क्रमोन्नति पदोन्नति देने की व्यवस्था रखी गई है। आखिर यह कहां तक न्याय संगत है। जब भी विभागों में रिक्त पद होते हैं वहां सीधी भर्ती कर उक्त कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जाता है। जबकि यह कर्मचारी उन्हीं रिक्त पदों का कार्य करते हैं जिन की सीधी भर्ती की तैयारी विभाग के आला अफसर कर जो आपके कार्य कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ करते हैं।

एंकर स्टोरी | हिंदी-इंग्लिश समेत 12 क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन होगा एग्जाम

केंद्रीय पशु पालन मंत्रालय गाय पर कराएगा परीक्षा

नई दिल्ली, जेएनएन। केंद्रीय पशु पालन मंत्रालय के अधीन आने वाले राष्ट्रीय कामधेनु आयोग पहली बार देश में गौ विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन वल्लभभाई कथीरिया ने बताया है कि अब यह परीक्षा हर साल कराई जाएगी। इस परीक्षा में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकेगा। इसके लिए कामधेनु आयोग के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम 25 फरवरी, 2021 से राष्ट्रीय स्तर पर कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा कराने जा रहे हैं। परीक्षा का मकसद लोगों में गायों के वैज्ञानिक फायदे के बारे में जागरूक करना है। खास बात यह है हिंदी-इंग्लिश के अलावा यह परीक्षा 12 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये भी बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जबकि पहले तीन स्थानों पर आने वाले लोगों को अवॉर्ड भी दिया जाएगा।

गाय से जुड़ीं खास बातें

- कुछ वक्त पहले राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि गाय का गोबर एंटी रेडिएशन है। इसे घर लाने से वह जगह भी रेडिएशन फ्री हो जाती है। वैज्ञानिक रूप से भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है, जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। जबकि इंसान के साथ अन्य प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बनडाई ऑक्साइड छोड़ते है। पेड़-पौधे कार्बन डाई ऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
- देशी गाय के गोबर में जीवाणु की भरमार होती है। देशी गाय के एक ग्राम गोबर में कम से कम 300 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं।
- गाय का दूध काफी गुणकारी माना जाता है। इसमें 7 एमीनोएसिड प्रोटीन पाया जाता है। इससे हड्डियों का रोग नहीं होता है।
- गाय के दिल की धड़कन एक मिनट में 60 से 70 होती है।
- गाय में चार तरह से डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट होते हैं।

इस तरह चार लेवल में आयोजित होगी परीक्षा

यह परीक्षा चार लेवल में आयोजित की जाएगी। प्राइमरी लेवल पर 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए, 9वें से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए, इसके बाद 12वीं के बाद पढ़ रहे स्टूडेंट्स और चौथा आम लोगों के लिए। परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा और सभी सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। परीक्षा के लिए एक सिलेबस और पाठ्य सामग्री भी तैयार की गई है, जिसे जल्द ही आयोग के वेबसाइट पर डाला जाएगा।

Badri Gautam

ज्ञापन दिया, निजी स्कूलों से पुस्तकों की सूची सार्वजनिक करने की मांग

भोपाल। 9वीं से 12वीं के स्कूल खुल गए हैं। प्राइवेट स्कूलों में अगले सत्र की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आरोप है कि प्रशासन का कोई आदेश नहीं होने से प्राइवेट स्कूल फिक्स दुकानों से पुस्तक खरीदने के लिए पुरानी सूची बदलकर नई सूची तैयार कर रहे हैं। इससे परेशान छोटे पुस्तक विक्रेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है। एक पुस्तक विकेता एमएस खान ने कलेक्टर को शिकायत करते हुए कहा है कि बड़े स्कूल पुस्तकों की सूची हर साल बदल देते हैं। पुस्तक विक्रेताओं ने कलेक्टर से मामले में संज्ञान लेते हुए स्कूलों को सूची सार्वजनिक करने और डीईओ कार्यालय में भेजने के आदेश देने की मांग की है।

Badri Gautam

कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ऑनलाइन एग्जाम की मांग

डीपीएस में ऑफलाइन एग्जाम को लेकर पैरेंट्स बिफरे, डीईओ से की शिकायत

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231327

कोलार रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) प्रबंधन और पैरेंट्स फिर आमने-सामने हैं। नया विवाद ऑफलाइन एग्जाम को लेकर है। पैरेंट्स की शिकायत है कि कोरोना काल में स्टूडेंट्स की जान जोखिम में डालकर ऑफलाइन एग्जाम के लिए उन्हें स्कूल बुलाया जा रहा है। पैरेंट्स ने गुरुवार को इसकी शिकायत डीईओ नितिन सक्सेना से भी की है।

दरअसल, डीपीएस प्रबंधन ने सभी स्टूडेंट्स की स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। पैरेंट्स को नोटिस देकर बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम के लिए स्कूल भेजने को कहा गया है। इसको लेकर पैरेंट्स ने हाल ही में स्कूल पहुंचकर प्राचार्य से आपत्ति भी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि अभी कोरोना का खतरा बना हुआ है। बच्चों की क्लास ऑनलाइन चल रही है, इसलिए एग्जाम भी ऑनलाइन कराए जाएं। स्कूल में सुनवाई नहीं होने से नाराज पैरेंट्स ने गुरुवार को डीईओ को ज्ञापन सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि वह हस्तक्षेप कर स्कूल प्रबंधन से कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए कहें।

Badri Gautam
डीपीएस में ऑफलाइन एग्जाम कराए जाने को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते पैरेंट्स।

कई स्टूडेंट्स ठीक से नहीं लगाते हैं मास्क।

क्या है गाइडलाइन

कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर जो गाइड लाइन जारी की है, उसमें स्पष्ट है कि 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाएं लगाई जाएंगी, लेकिन पैरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। जो स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्लास और एग्जाम की व्यवस्था करनी होगी।

संक्रमण को न्योता: स्कूल में कोरोना गाइड लाइन का पालन नहीं हो रहा है। खुद टीचर ही सही तरीके से मास्क नहीं लगा रहे हैं। बच्चों से भी इसका पालन नहीं कराया जा रहा है।

ऑफलाइन एग्जाम लेना गलत

दिल्ली पब्लिक स्कूल सहित प्रायः सभी प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास के नाम पर साल भर फीस वसूली। जब इन स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई की फीस ली है, तो अब बच्चों की जान जोखिम में डालकर ऑफलाइन एग्जाम कराया जाना गलत है।

प्रबोध कुमार पण्डया, महासचिव, मप्र पालक महासंघ

हम गाइडलाइन फॉलो कर रहे

हम शासन द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। हम ऑनलाइन सुविधा भी बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं। इस मामले में पैरेंट्स का अपना-अपना व्यू है।

वंदना धूपड़, प्राचार्य, डीपीएस

कुछ पैरेंट्स ने शिकायत की है

कुछ पैरेंट्स ने डीपीएस के खिलाफ शिकायत की है कि ऑनलाइन की फीस लेकर ऑफलाइन एग्जाम कराए जा रहे हैं। हमने नोटिस दिया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

नितिन सक्सेना, डीईओ, भोपाल

छात्रावास को खोले जाने की मांग

छात्र-छात्राओं ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

पीपुल्स संवाददाता ● विदिशा
मो.नं. 9981697996

Badri Gautam

एससी, एसटी और ओबीसी छात्रावासों को खोले जाने की मांग को लेकर एक बार फिर छात्र-छात्राओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। दुर्गानगर महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा होकर जिलेभर से आए छात्र-छात्राओं ने रैली की शक्ल में कलेक्टोरेट पहुंचकर मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह को सौंपा।

जिसमें कहा गया कि पूरे देश में कोविड के चलते जब सबकुछ बंद था तब छात्रावास भी बंद कर दिए गए थे। अब जबकि सबकुछ सुचारू से चालू हो चुका है। स्कूल और कालेज भी खुलने लगे हैं तब विद्यार्थी दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों से जिला मुख्यालय पर आकर स्कूलों में पढ़ने के बाद अपने घर जाकर पढ़ाई व्यवस्थित रूप से नहीं कर पा रहे हैं। पहले की तरह यदि छात्रावास खुल जाएं तो उनकी पढ़ाई की बाधा दूर हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने आवास योजनांतर्गत छात्र-छात्राओं को मिलने वाली राशि का भी भुगतान न होने की शिकायत की। ज्ञापन से उन्होंने 9 माह से बंद छात्रावासों को खोले जाने की बात कही है।

20 छात्राओं को नहीं मिला गांव की बेटी व प्रतिभा किरण योजना का लाभ

रीवा। गांव की बेटी व प्रतिभा किरण योजना की पात्र 20 छात्राओं को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला। सत्र 2019-20 में कोरोनाकाल के चलते उक्त छात्राएं लाभ से वंचित रह गईं। एडी रीवा क्षेत्र के महाविद्यालयों की इन छात्राओं को शीघ्र योजना से लाभान्वित करने के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग ने दिए हैं। विभाग के निर्देशानुसार सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ रहे पात्र छात्रों को योजनाओं का लाभ दिया जाना है। इस बाबत विभाग ने पहले भी आदेश जारी किए हैं। आदेश में विभाग ने उल्लेखित किया है कि गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, विक्रमादित्य जैसी योजनाओं के पात्र छात्रों को ऑनलाइन भुगतान किया जाये, ताकि सभी पात्र छात्र योजना से लाभान्वित हो सके। उक्त प्रक्रिया होने के बाद सत्र 2020-21 के छात्रों को भी समय पर योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु निर्देशित किया गया है। गौरतलब है कि चालू सत्र की प्रवेश प्रक्रिया हाल ही में खत्म हुई है। यह प्रवेश प्रक्रिया पहले ही एक माह की देरी से शुरू हुई। इधर, लॉकडाउन के चलते कई छात्रों के परिवारजन अभी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे में छात्रों को समय पर योजनाओं का लाभ मिलने से उनका भार कुछ कम होगा और छात्रों को पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। विभाग ने छात्रों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही के निर्देश प्राचार्यों को दिए हैं। समय पर छात्रों का भुगतान न होने पर विभाग ने प्राचार्य व अग्रणी महाविद्यालय प्राचार्य की जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा है।

Badri Gautam

चालान को स्वीकार करने के लिए कोर्ट में 28 को सुनवाई

व्यापमं घोटाले में 60 लोगों के खिलाफ चालान पेश

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

सीबीआई ने गुरुवार को विशेष सत्र न्यायालय में चिरायू मेडीकल कालेज, तत्कालीन डीएमई सहित 60 लोगों के खिलाफ चालान पेश कर दिया। इस पूरक चालान में 57 नए आरोपित हैं और तीन पुराने हैं। इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा अलग से लगाई है। वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट ने आरोपितों को पांच-पांच करके बुलाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के इस आदेश के आने के बाद आरोपितों के गिरफ्तारी वारंट नहीं निकल सके। विशेष न्यायालय पांच-पांच करके आरोपितों को कोर्ट में बुलाएगा। चालान को स्वीकार करने के लिए 28 जनवरी की तारीख निर्धारित की है।

चिरायू मेडीकल कालेज में शासन कोटे की 63 सीटें थी। वर्ष 2011 में 47 सीटों को गलत तरीके से खाली रखा गया। चिरायू मेडीकल कालेज का प्रबंधन मोटी रकम लेकर सीटों को बेच दी। ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया, जिन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था। व्यापमं कांड के खुलासे के वक्त झांसी रोड थाने में तीन लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। एसआइटी ने तीन लोगों के खिलाफ चालान पेश कर चुकी थी। वर्ष 2015 में यह केस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआइ के हैंडओवर हो गया। सीबीआई ने पांच साल इस मामले की जांच की। पांच साल की जांच में 57 नए आरोपित बनाए गए हैं। सरकारी कोटे की सीट छोड़ने वाले, सीट खरीदने वाले, चिरायु मेडीकल कालेज के प्रबंधन के अधिकारी, बिचौलियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 60 लोगों के खिलाफ चालान पेश कर दिया। बताया जाता है कि सीबीआई ने करीब 5 हजार पन्नों का अभियोग पत्र बनाया है। जिसमें आरोपियों ने किस किस तरह से सरकारी कोटे की सीटों का अपने हित के लिये उपयोग किया है।

Badri Gautam

कोविड-19 के तहत स्कूली बच्चों से कराई गतिविधियों का मांगा ब्योरा

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने कोविड-19 के तहत कराई गई गतिविधियों का डाटा जिलों से जुटाना शुरू कर दिया है। राज्य शिक्षा केंद्र अपर संचालक ओएल मंडलोई ने प्रदेशभर के डीपीसी को जानकारी एक सप्ताह में भेजने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त संचालक ने अपने आदेश में कहा है कि समग्र शिक्षा अभियान की आगामी वर्ष की कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों द्वारा कोविड-19 के तहत वर्तमान वर्ष में संपन्न कराई गई गतिविधियां मय फोटो ग्राफ तैयार कर भेजी जाएं।

Badri Gautam

डीईओ ने किया विद्यालय व पीडीएस दुकानों का निरीक्षण

बैराड़, नि.प्र.

जिला शिक्षा अधिकारी दीपक पाण्डे ने गुरुवार को बैराड़ नगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर बीआरसी अचल सिंह कुशवाह भी उनके साथ थे। डीईओ ने विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य को समस्त छात्रों को ब्लूप्रिंट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जारी कोविड-19 गाइड लाइन के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार कक्षाएं लगाई जाएं और समय-सीमा में कोर्स पूर्ण कराया जाए। नियमित समय पर कक्षाएं लगाई जाएं। उन्होंने विद्यालय में छात्र-छात्राओं की कॉपियां भी देखीं और छात्र-छात्राओं से चर्चा भी की। तत्पश्चात डीईओ ने बैराड़, भदेरा, कालामढ़ की उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानों पर अन्न उत्सव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उचित मूल्य की दुकानों पर मशीन से निकल रही पर्चियों का भी का अवलोकन किया और स्टाफ के बारे में जानकारी ली।

Badri Gautam

स्कूल विद्या का मंदिर है, इसे साफ-सुथरा और सुंदर रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी:कलेक्टर

● कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला का हुआ आयोजन

Badri Gautam

रीवा(नव स्वदेश)। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियों के क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में नगर को स्वच्छ बनाने में शासकीय तथा अशासकीय स्कूलों की भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यशाला में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा कि नगर को स्वच्छ रखना सबकी जिम्मेदारी है। सबके सहयोग से ही रीवा शहर साफ-सुथरा और सुंदर बनेगा। इसके लिये प्रत्येक नागरिक का स्वच्छता के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। लोगों को जागरूक करने में स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्कूल के विद्यार्थियों के माध्यम से हर घर में स्वच्छता का संदेश पहुंचाया जा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि सभी प्राचार्य तथा प्रधानाध्यापक अपने स्कूलों में साफ-सफाई का विशेष अभियान चलायें। स्कूलों को साफ-सुथरा बनाकर उपयुक्त स्थानों पर स्वच्छता संदेशों की वाल पेंटिंग करायें। स्कूल के विद्यार्थियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करके भी स्वच्छता का संदेश दिया जा सकता है। शिक्षक तथा विद्यार्थी मिलकर स्कूल के आसपास के पार्क अथवा अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थल की भी साफ-सफाई तथा सौन्दर्यीकरण में योगदान दे सकते हैं। स्कूल विद्या के मंदिर होते हैं। इन्हें साफ-सुथरा तथा सुंदर रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। नगर निगम के अधिकारी तथा कर्मचारी स्कूलों को साफ-सुथरा बनाने में पूरा सहयोग देंगे। कार्यशाला में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा ने कहा कि सभी शिक्षक तथा विद्यार्थी अपने मोबाइल पर स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लें। इसके माध्यम से स्वच्छता के संबंध में किये जा रहे अच्छे प्रयासों तथा इससे जुड़ी समस्याएं दर्ज की जा सकती हैं। कार्यशाला में अधीक्षण यंत्री शैलेन्द्र शुक्ला, कार्यपालन यंत्री एसके चतुर्वेदी, स्वच्छता अभियान के नोडल दिग्विजय सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी आरएन पटेल तथा नगर निगम क्षेत्र के शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के प्राचार्य शामिल हुए।

आयुष काउंसलिंग: आज होगा सीट आवंटन, 11 तक लेना होगा प्रवेश

भोपाल। बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस स्नातक में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की स्टेट नीट आयुष काउंसलिंग में गुरुवार को सीट अलॉटमेंट होगा। छात्र 8 से 11 जनवरी तक संबंधित आयुष कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, इंदौर, बुरहानपुर, उज्जैन के साथ प्रदेश के विभिन्न आयुष कॉलेजों के 1200 स्नातक सीटों पर काउंसलिंग चल रही है।

एडमिशन

Badri Gautam

ओआईसी ने किया निरीक्षण, अनुपस्थित मिले शिक्षक

रमसा प्रभारी ने बैकुंठपुर कन्या स्कूल का किया निरीक्षण, क्लास भी ली

जागरण, रीवा। भोपाल संचालनालय से रीवा आए ओआईसी ने गुरुवार को पिड़रिया सेंगर, बहेरा डाबर, ढेरा स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई शिक्षक स्कूल से नदारद मिले। प्रायोगशाला निरीक्षण में क्रियाशील नहीं मिली। इस पर नाराजगी जताई है। इसके अलावा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक रमसा डॉ पीएल मिश्रा ने भी स्कूलों का निरीक्षण किया। मौके पर छात्रों की क्लास भी ली। गुरुवार को लोक शिक्षण संचालनालय से नियुक्त ओआईसी सुरेश त्रिपाठी उप संचालक संचालनालय ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढेरा, शासकीय हाई स्कूल पिड़रिया सेंगर और हाई स्कूल बहेरा डाबर का आकस्मिक निरीक्षण किया। शाउमावि ढेरा में मोहनलाल कोल प्रधानाध्यापक, अशोक कुमार शुक्ला सहायक शिक्षक, रघुवीरशरण तिवारी सहायक शिक्षक विज्ञान, शिवबहोर द्विवेदी सहायक शिक्षक विज्ञान एवं राजेश अहिरवार भृत्य मौके से नदारद रहे। शासकीय हाई स्कूल बहेरा डाबर में अतिथि शिक्षक शिवभान मिश्रा एवं सचिन सिंह भी नदारद रहे। ओआईसी के निरीक्षण में इन विद्यालयों में कक्षाएं संचालित तो पाई गईं लेकिन प्रयोगशालाएं क्रियाशील नहीं मिली। छात्रों को गृह कार्य दिया जाना एवं गृह कार्य को चेक करने का निर्देश भी दिया गया। मप्र शासन की कोविड 19 के एसओपी का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। इसी तरह गुरुवार को अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक रमसा डॉ पीएल मिश्रा ने शासकीय उमावि कन्या बैकुंठपुर, शासकीय हाई स्कूल चचाई का निरीक्षण किया। कन्या बैकुंठपुर में डॉ पीएल मिश्रा ने कक्षाएं भी ली। छात्रों को पढ़ाया भी। इसके अलावा चचाई में नए हाई स्कूल भवन का भूमि पूजन भी कराया। आनलाइन शाउमावि मनगवां का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में छात्रों की उपस्थिति कम मिली। इस पर प्राचार्यों को अभिभावकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

रीवा में दर्दनाक हादसा: स्कूल बस पर पलटा क्लींकर लदा ट्रेलर, तीन शिक्षकों की मौत

भास्कर न्यूज . रीवा| गोविंदगढ़ थाना अन्तर्गत छुहिया घाटी में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की स्कूल बस पर क्लींकर लदा ट्रेलर पलट गया। जिससे बस में सवार 9 शिक्षकों में 3 की मौत हो गई। बताया जाता है कि सीमेंट क्लींकर गर्म था। जिसकी चपेट में आकर शिक्षक झुलस भी गए हैं।

जानकारी अनुसार, अल्ट्राटेक सीमेंट की स्कूल बस एमपी 17 पी 1170 रीवा से 9 शिक्षकों को लेकर सीधी के बघवार स्थित सरदार पटेल स्कूल जा रही थी। सुबह करीब 7.30 बजे बस छुहिया घाटी में एक मोड़ पर सड़क किनारे खड़ी थी।

Badri Gautam

तभी क्लींकर लदा ट्रेलर एमपी 66 एच 1767 बगल से गुजर रहा था। उसकी रफ्तार काफी तेज थी। जो अचानक अनियंत्रित हो गया और सीधे बस पर पलट गया।

शेष | पेज 12 पर (पेज 5 भी देखें)

मौत ने बदल ली सीट

स्पोर्ट्स टीचर हरिकिशन मिश्रा की किस्मत अच्छी थी, जो हादसे में बाल-बाल बच गए। ऐन वक्त पर मौत ने सीट बदल ली और उनकी जान बच गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद उनके एक मित्र ने फोन लगा हालचाल पूछा तो उन्होंने बदहवासी में हादसे की आपबीती साझा की। उन्होंने मित्र को बताया कि मैं जिस सीट पर बैठकर प्रतिदिन स्कूल जाता था, गुरुवार को उस सीट पर नहीं बैठा। जब मैं बस पर सवार हुआ था तो पाया कि टीचर प्रतिभा पाण्डेय पहले से मेरी सीट पर बैठी थीं। जब मैं सीट के करीब पहुंचा तो वो उठने लगी, तो मैंने कहा कि आज आप बैठे रहिए, कल मैं फिर से इस सीट पर बैठ जाऊंगा और एक सीट आगे बैठ गया। जब क्लींकर का ट्रेलर बस पर पलटा, तो टीचर प्रतिभा बाल-बाल बच गईं।

वर्कशीट पर होगा छमाही परीक्षा का मूल्यांकन

भास्कर न्यूज | सतना राज्य शिक्षा केन्द्र ने आयोजित होने वाली प्रतिभा पर्व (छमाही परीक्षा) का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके तहत छात्रों का मूल्यांकन वर्कशीट पर कराया जाएगा। छमाही परीक्षा के लिए यह कार्यक्रम 20 से 30 जनवरी के मध्य आयोजित होगा, जिसके प्रत्येक विषय का पूर्णांक 20 अंक का होगा। इसी प्रकार वार्षिक मूल्यांकन में फरवरी में दो वर्कशीट हर छात्र-छात्राओं को दी जाएगी, जिनके पूर्णांक 50 अंक के होंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक की परीक्षा के लिए इस बार अलग से गाइड लाइन तैयार की गई है। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार वर्कशीट का मुद्रण जिलास्तर पर कराया जाएगा, जिसका वितरण शिक्षकों को एक साथ करना होगा, जिसमें छमाही परीक्षा के साथ-साथ वार्षिक परीक्षा की वर्कशीट भी शामिल होंगी।

स्कूल नहीं आएंगे छात्र

वर्कशीट पर छात्रों द्वारा अपने प्रश्नों को हल कर उन्हें वापस अपने शिक्षक के पास जमा करनी होगी, लेकिन किसी भी स्थिति में छात्र स्कूल नहीं आएंगे। शिक्षकों को छात्रों से सम्पर्क कर उनके घरों से वर्कशीट जमा करनी होगी। बताया गया कि छात्रों को वर्कशीट तो एक साथ दे दी जाएगी, लेकिन उनसे मूल्यांकन कार्य के तय समय के अनुसार वर्कशीट वापस जमा कराई जाएगी। बताया गया कि वर्कशीट में छमाही परीक्षा के जो अंक शिक्षकों द्वारा छात्रों को दिए जाएंगे, वह अंक वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन में जोड़े जाएंगे। इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जिले के समस्त मॉनीटरिंग अमले को स्कूलों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि छात्रों के मूल्यांकन कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न हो सके।

Badri Gautam

स्कूल से हजारों का सामान पार

सतना | मैहर थाना अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय उदयपुर में पांच दिन के भीतर 3 बार चोरी हो गई। हेडमास्टर के द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि अज्ञात बदमाशों ने 28 दिसम्बर की रात को मुख्य दरवाजे का हेलड्राप काट दिया तो 31 दिसम्बर की रात उसी गेट का दूसरा हेलड्राप क्षतिग्रस्त कर दिया, तब रिंग डालकर ताला बंद किया गया, मगर चोरों ने 1 जनवरी की रात को रिंग काटकर कार्यालय में रखी पेटी के कुंदे को अलग कर दिए और थाली, चम्मच, बाल्टी, प्लेट, कढ़ाई और पुराने रजिस्टर समेत हजारों का सामान पार कर दिया। हेडमास्टर की शिकायत पर पुलिस ने कायमी कर जांच शुरू कर दी है। वारदात में स्थानीय बदमाशों का हाथ होने की आंशका बताई गई है।

Badri Gautam

एमपी बोर्ड : अब कॉपियां जिले में ही जांचने की तैयारी

भोपाल। एमपी बोर्ड अब बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी जांचने और मूल्यांकन में भी बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है, जिसके अनुसार अब जिले में ही कॉपियां जांची जाएंगी। ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जा सके। साथ ही जिस-जिस विषय की कॉपियां जांची जाएंगी, उस विषय का रिजल्ट समन्वयक केंद्रों से बोर्ड को ऑनलाइन भेजा जाएगा, जिससे विषयवार रिजल्ट भी माशिमं की वेबसाइट पर प्रदर्शित होने लगेगें। साथ ही विषयवार कॉपियों का परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

Badri Gautam

अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हो सकती हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं

भास्कर न्यूज | सतना

शैक्षणिक सत्र 2020-21 में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आयोजित कर सकता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की समन्वयक संस्था व्यंकट क्रमांक-1 के प्राचार्य गोपालशरण सिंह की मानें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल से ऐसे संकेत मिल रहे हैं परीक्षाएं दो माह आगे आयोजित होंगी। इस बार सप्लीमेंट्री परीक्षा का प्रावधान नहीं रहेगा। इसके अलावा

कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऐसी भी कार्ययोजना पर विचार चल रहा है कि छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा कराई जाए, हालांकि इसके लिए अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। प्री-बोर्ड परीक्षाओं के ट्रायल के बाद ही माध्यमिक शिक्षा मंडल इन नियमों को लागू करेगा।

दो बार होंगी परीक्षाएं

माध्यमिक शिक्षा मंडल इस बार पूरक परीक्षा आयोजित नहीं करेगा, जबकि बोर्ड की परीक्षाएं दो बार आयोजित की जाएंगी। छात्र दोनों में से किसी एक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इस साल जिले से करीब 80 हजार छात्रों ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पंजीयन किया है। बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू होकर मई तक चलेंगी। दूसरी बार परीक्षा इसके तीन महीने बाद होगी। दोनों मुख्य परीक्षा ही होंगी। पहली बार में फेल होने वाले छात्र दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, उन्हें इसके लिए अगले साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

ट्रायल के लिए प्री-बोर्ड

बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 18 दिसंबर को स्कूल खोले गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2021 की बोर्ड परीक्षा में 30 फीसदी प्रश्न ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पूछने का फैसला किया है। तीन घंटे की परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं होंगे। सभी विषयों की परीक्षा में 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बोर्ड ने कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। इसके ट्रायल के लिए प्री-बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की तैयारी हो रही है। इसके आधार पर बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करने के बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किए प्रश्न बैंक

शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 के प्राचार्य गोपालशरण सिंह ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं एवं 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए प्रश्न बैंक जारी कर दिए गए हैं, जिसे शिक्षा मंडल की बेवसाइट पर लोड भी कर दिया गया है। कुछ ही दिनों में छात्रों को सभी विषयों के प्रश्न बैंक उपलब्ध हो जाएंगे। बताया गया कि बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक से विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आसानी हो जाती है। वहीं माना जाता है की बोर्ड परीक्षा में कई प्रश्न, प्रश्न बैंक से ही पूछे जाते हैं। कोरोना काल की वजह से जहां विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हुई है। वहीं प्रश्न बैंक उनकी परीक्षा की सफलता में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

Badri Gautam

स्वच्छता में शहर को पहले पायदान पर लाने के लिए 90 हजार विद्यार्थियों को करेंगे प्रेरित

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर नगर निगम ने पहले पायदान पर आने की तैयारी शुरू कर दी है। वीते साल लोगों द्वारा दिए जाने वाले फीडवैक में पीछे रहे भोपाल ने नया तरीका निकाला है। इसके तहत कम से कम शहर से पांच लाख लोगों का फीडवैक लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गुरुवार को शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संभागायुक्त व नगर निगम प्रशासक कवींद्र कियावत और निगमायुक्त वीएस चौधरी कोलसानी ने संकुल प्राचार्य, प्राध्यापकों व अध्यापकों के साथ इस संबंध में वैठक की। इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों व छात्रों को फीडवैक देने के लिए प्रेरित किया।

सर्वेक्षण 2021 की तैयारी

- **संभागायुक्त व निगमायुक्त ने शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ की बैठक**
- **छात्र-छात्राओं को फीडवैक देने के लिए किया जाएगा जागरूक**

संभागायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि शहर में करीव 90 हजार छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। लिहाजा शहर के प्रति दायित्व निभाते हुए इन्हें फीडवैक देने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को नींद से जगाना वेहद जरूरी है। स्वच्छता में हर स्तर पर लोगों को जोड़ने से वेहतर परिणाम मिलेंगे और भोपाल नंवर एक जरूर वनेगा। वैठक में शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक राजीव सिंह तोमर, जिला शिक्षा अधिकारी नितिन चतुर्वेदी समेत नगर निगम अधिकारी मौजूद रहे।

संभागायुक्त ने कहा कि स्वच्छता के लिए सभी को एक साथ जुटना होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण के कुल छह हजार अंकों में 300 सिर्फ फीडवैक के निर्धारित किए गए हैं। भोपाल को देश का सवसे स्वच्छ शहर वनाने के लिए 1969 पर कॉल करें और पूछे गए प्रश्नों का सकारात्मक जवाव दें। साथ ही दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। निगमायुक्त ने कहा कि नगर निगम द्वारा फीडवैक के लिए पूछे गए सवालों को लेकर भी जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने स्वच्छता महुआ एप के जरिये व्यवस्थाओं में सुधार के लिए भी लोगों से अपील की।

Badri Gautam

एमपीपीएससी **कोचिंग संचालक बोले- एक जनवरी 2020 से होनी चाहिए आयु गणना नहीं तो विद्यार्थियों को होगा नुकसान**

परीक्षा के लिए आयु गणना में एक साल की मिले छूट

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। मप्र लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) 2020 परीक्षा के लिए आवेदन 11 जनवरी से शुरू हो जाएंगे, जो एक माह तक चलेंगे। पीएससी परीक्षा के लिए आयु की गणना में एक साल की छूट के लिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। कोचिंग संचालकों का कहना है कि शासन वर्ष 2020 में पीएससी की परीक्षा नहीं करा पाया इससे अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। ऐसे कई अभ्यर्थी हैं, जो एक जनवरी 2021 से आयु की गणना होने से वर्दीधारी पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। साथ ही इस बार सभी विभागों में पदों की संख्या भी कम प्रदर्शित की गई है। इससे वर्षों से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी निराश होंगे। वहीं, पांच-छह साल से पीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की मांग है कि पिछले साल की तरह इस साल भी आयु गणना में संशोधन किया जाए। अगर एक जनवरी 2021 से आयु गणना की जाएगी तो इससे प्रदेश से करीब 10 से 15 हजार अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में वो जनवरी 1981 से पहले की जन्मतिथि वाले अभ्यर्थी राज्य सेवा परीक्षा के किसी भी पद के लिए पात्र नहीं होंगे।

कोचिंग संचालकों का कहना है कि इस बार विभिन्न विभागों में कम संख्या में रिक्तियां निकाली गई हैं, जहां राज्य वन सेवा में 111 पद है तो राज्य सेवा परीक्षा के लिए 235 पदों की रिक्तियां निकाली गई हैं। इसका कारण यह है कि विभाग अपने यहां की रिक्तियों की जानकारी आयोग को समय से नहीं भेजते हैं। इस बार तो बहुत कम रिक्तियां उपलब्ध कराई गई हैं। इससे अभ्यर्थियों में निराशा होगी।

अभ्यर्थियों को तैयारी का नहीं मिलेगा समय : पीएससी 2019 मेंस की परीक्षा मार्च में होगी और उसके एक माह बाद अप्रैल में 2020 की प्रारंभिक परीक्षा होगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को दोनों परीक्षा की तैयारी करने के लिए समय नहीं मिल पाएगा। पीएससी को अपना कैलेंडर सही करना चाहिए। कैलेंडर का सही पालन इसलिए नहीं हो पाता है, क्योंकि सभी विभाग अपने यहां की रिक्तियों को समय पर आयोग में नहीं भेजते हैं।

मैं अपनी जॉब छोड़कर पीएससी की तैयारी में लगा हूं, लेकिन इस बार आयु की गणना एक साल बढ़ाकर मांगी जा रही है। अगर आयु की गणना एक साल कम नहीं की गई तो वर्दीधारी पदों के लिए कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। **- कमल वागवान**, अभ्यर्थी

सरकार की गलती है कि पिछले साल की पीएससी परीक्षा को एक साल देरी से ले रही है। ऐसे में 2020 पीएससी के लिए 2021 में परीक्षा ली जा रही है और आयु की गणना एक जनवरी 2021 से की जा रही है। इससे विद्यार्थियों को निराशा हो रही है।
-राजीव कुमार रंजन, कोचिंग संचालक

अगर आयु की गणना एक जनवरी 2020 से कर दें तो कई अभ्यर्थी पात्र हो जाएंगे। मैं भी वर्दीधारी पद पर आवेदन करने के लिए पात्र हो जाऊंगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अभ्यर्थियों को नुकसान होगा।
- पीयूष शुक्ला, अभ्यर्थी

कोविड-19 के कारण पीएससी में आयु की समय सीमा में दो-तीन साल की छूट देनी चाहिए। कम से कम एक साल तो छूट जरूर देनी चाहिए। जब पीएससी 2020 की परीक्षा है तो आयु की गणना एक जनवरी 2020 से होनी चाहिए। **-संजय तिवारी**, अध्यक्ष, मप्र कोचिंग वेलफेयर एसोसिएशन

Badri Gautam

तीन हजार अतिरिक्त सीएम राइज स्कूलों का सत्यापन कर विभाग को भेजा

भोपाल (नप्र)। प्रदेश के स्कूलों को सर्वसुविधायुक्त बनाने के लिए उत्कृष्ट विद्यालयों की तर्ज पर दस हजार स्कूलों का कायाकल्प किया जाना है। पहले चरण में एक जनशिक्षा केंद्र से तीन स्कूलों को विकसित कर सर्वसुविधायुक्त बनाया जाएगा। सीएम राइज नाम से विकसित किए जाने वाले 9 हजार 985 स्कूलों का जनशिक्षा केंद्र स्तर से चयन करने का लक्ष्य दिया गया था। तय समय सीमा में पहले तो जिलों ने सत्यापन का काम नहीं किया। जब राज्य स्तर से अधिकारियों ने फटकार लगाई तो जिलों ने लक्ष्य से तीन हजार अतिरिक्त स्कूलों का सत्यापन कर विभाग को भेज दिया। लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त जयश्री कियावत ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर डाइस डाटा के अनुसार चिह्नित शालाओं के प्राप्तांक स्कोर के हिसाब से लक्ष्य के अनुसार स्कूलों का चयन करने के आदेश दिए हैं।

Badri Gautam

कई बार ट्रायल करने के बाद ऑनलाइन परीक्षा करा पाया एसजीएसआइटीएस

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर के श्री गोविंदराम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एसजीएसआइटीएस) ने कोरोना महामारी में अपने 3500 विद्यार्थियों की परीक्षा सफलतापूर्वक ऑनलाइन प्रक्रिया से करा ली है। इसके बाद अब संस्थान विचार कर रहा है आगे की परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही कराई जाए। इससे विद्यार्थियों का समय और संस्थान का पैसा बचेगा। पहली बार बड़े स्तर पर ऑनलाइन परीक्षा संस्थान ने कराई थी।

परीक्षा के लिए संस्थान ने अपने आइटी और अन्य विभागों की मदद से ऐसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया, जिससे सर्वर धीमा न हो और हजारों विद्यार्थियों की कॉपी अपलोड करने और अन्य प्रक्रिया आसानी से हो जाए। चूंकि संस्थान के पास खुद के आइटी इंजीनियर हैं, ऐसे में बाहर की कंपनियों को परीक्षा कराने के लिए ज्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ा।

परीक्षा का मामला

- **साढ़े तीन हजार विद्यार्थियों की परीक्षा बिना किसी परेशानी कराई**
- **ऑनलाइन परीक्षा में दूसरे संस्थानों की भी करेगा मदद**

Badri Gautam

दूसरे संस्थानों को भी मदद करेंगे : संस्थान के निदेशक डॉ. आरके सक्सेना का कहना है हमने ऑनलाइन परीक्षा को एक चुनौती की तरह लिया और इसमें सफल रहे। कोरोना महामारी में ज्यादातर विद्यार्थी अपने घर चले गए हैं। ऑनलाइन माध्यमों से ही उनकी कक्षाएं ली जा रही हैं। हमने परीक्षा कराने के एक महीने पहले से ऑनलाइन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू कर दिया था।

इसके लिए कई बार ट्रायल किए गए ताकि एक भी विद्यार्थी परीक्षा देने से न रह जाए। विद्यार्थियों को प्रश्नों के जवाब देने के लिए निश्चित समय दिया गया और कॉपी को अपलोड करने के लिए कहा गया। हमारा परीक्षा का ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह सफल रहा है। अब हम इसे आगे की परीक्षाओं में भी लागू करने पर विचार कर रहे हैं। दूसरे संस्थानों को भी हम मदद करेंगे, ताकि वे भी विद्यार्थियों की परीक्षा ऑनलाइन करा सकें।

शोध शुरू होने से पहले सेंटर मांग रहे फीस विश्वविद्यालय नोटिस देने की तैयारी में

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। दो साल पहले पीएचडी में प्रवेश ले चुके विद्यार्थी अब तक शोध शुरू नहीं कर पाए हैं। मगर रिसर्च सेंटर फीस मांगने लगे हैं। नाराज विद्यार्थियों ने कुलपति से सेंटर की मनमानी को लेकर शिकायत कर दी है। अधिकारियों ने सेंटर के जिम्मेदारों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। यहां तक संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन सेंटर को नोटिस थमा सकता है। वहीं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. रेणु जैन ने जल्द ही सेंटर प्रभारियों की बैठक बुलाने का फैसला लिया है।

2018 में डीईटी के जरिए पीएचडी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों ने कोर्स वर्क पूरा कर लिया। मगर इसके बाद रिसर्च डिपार्टमेंट कमेटी (आरडीसी) की बैठक नहीं हुई। इससे विद्यार्थी अपना शोध कार्य शुरू नहीं कर सके। बावजूद इसके रिसर्च सेंटर लॉकडाउन के बाद से विद्यार्थियों से फीस मांग रहे हैं। विद्यार्थियों के मुताबिक प्रत्येक सेंटर चार से छह हजार रुपये सेमेस्टर फीस जमा करने पर जोर दे रहा है। लगभग 12 से 18 हजार रुपये फीस का बोझ विद्यार्थियों पर आ चुका है। दो दिन पहले विद्यार्थियों ने आरडीसी नहीं होने और रिसर्च सेंटर की मनमानी को लेकर कुलपति के सामने विरोध जताया। विद्यार्थियों ने शोध कार्य शुरू होने से पहले फीस मांग रहे सेंटर पर कार्रवाई पर जोर दिया। उनका कहना था कि कोरोनाकाल में विद्यार्थियों के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। ऐसे में सेंटर फीस मांग कर दबाव बना रहा हैं। बताया जाता है कि कुलपति ने विद्यार्थियों को कमेटी के सामने फीस का मुद्दा उठाने की सलाह दी है। 30 फीसद विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के विभाग को रिसर्च सेंटर चुना है। जबकि अधिकांश ने निजी कॉलेजों में रहकर शोध करने की इच्छा जताई। कुलपति के निर्देश पर विवि सेंटर को नोटिस देने की तैयारी कर रहे है। प्रभारी रजिस्ट्रार अनिल शर्मा ने कहा कि सेंटर से जवाब मांग स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही कुलपति ने सेंटर प्रभारियों की बैठक बुलाई है।

Badri Gautam

फीस कम करने की मांग, वैष्णव स्कूल में पालकों का हंगामा

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। आधी फीस माफ करने की मांग और कुछ बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर किए जाने के विरोध में श्री वैष्णव ट्रस्ट के स्कूलों के पालकों ने हंगामा किया। दिनभर चले हंगामे के बाद प्रबंधन ने शनिवार को ट्रस्ट की बैठक के बाद निर्णय लेने को कहा है।

गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में पालक राजमोहल्ला चौराहे पर स्थित श्री वैष्णव ट्रस्ट के स्कूल पर पहुंचे। यहां ट्रस्ट द्वारा सीबीएसई स्कूलों का संचालन किया जाता है। पालकों का आरोप था कि ट्रस्ट के चार स्कूल हैं। ट्रस्ट की दुकान के किराए से भी बड़ी आय होती है फिर भी हमें फीस भरने में कोई राहत नहीं दी जा रही है। जबकि दूसरे कई स्कूल आधी फीस तक माफ कर चुके हैं। इसके अलावा मंगलवार को टीचरों ने कई विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास के ग्रुपों से बाहर कर दिया है। पालकों का यह भी कहना था कि कोरानाकाल में हम लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं ऐसे में स्कूल को हमारी परेशानी समझना चाहिए। इधर हंगामे के बाद स्कूल के स्टाफ ने आकर हंगामा कर रहे पालकों से चर्चा की, लेकिन पालक उनकी बात नहीं माने। सूचना मिलने पर एसडीएम और पुलिस भी पहुंची। शाम तक पालक स्कूल में बैठे थे।

ट्रस्ट का स्कूल हम क्या करें

स्कूल के स्टाफ ने पालकों से कहा कि हम आपकी परेशानी को समझ रहे हैं लेकिन आपके इस तरह से आने से हम लोग फीस नहीं माफ कर सकते। यह ट्रस्ट का स्कूल है। इस मामले की जानकारी ट्रस्ट के पदाधिकारियों को दे दी है।

Badri Gautam

शिक्षकों को तनख्वाह दी या नहीं, बहस तीन सप्ताह बाद

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। अभिभावकों से पूरी फीस वसूलने के बावजूद कई निजी स्कूलों ने शिक्षकों को पूरी तनख्वाह का भुगतान नहीं किया। इस संबंध में हाई कोर्ट में चल रही जनहित याचिका में गुरुवार को बहस होनी थी, लेकिन टल गई। अब कोर्ट मामले में तीन सप्ताह बाद सुनवाई करेगी। इसी दिन कोर्ट याचिकाकर्ता के संशोधन आवेदन पर भी बहस सुनेगी।

मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही इस जनहित याचिका में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से पूरी फीस वसूलने के बावजूद शिक्षकों को पूरी तनख्वाह नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया गया है। डेली कॉलेज जैसे स्कूल का नाम लेते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि कई स्कूलों के प्रिंसिपल अभिभावकों से वसूली जा रही फीस को मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी तनख्वाह नहीं मिलने से शिक्षक परेशान हो रहे हैं। स्कूलों द्वारा शिक्षकों को आवंटित क्वार्टर भी खाली करवाए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने शिक्षकों को आवंटित क्वार्टर खाली कराने पर रोक लगाते हुए डेली कॉलेज प्रिंसिपल से कहा था कि वे शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताएं कि जनवरी 2020 से अब तक किस शिक्षक को कितनी तनख्वाह दी गई है। पिछली सुनवाई पर प्रिंसिपल ने शपथ पत्र दिया था। इसमें उन्होंने कोर्ट को बताया है कि स्कूल प्रबंधन ने शिक्षकों को 80 प्रतिशत तनख्वाह का भुगतान कर दिया है। गुरुवार को इसी मुद्दे को लेकर बहस होनी थी, लेकिन टल गई। अब बहस तीन सप्ताह बाद होगी।

11 जनवरी तक जमा करनी हैं कॉपियां

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। पीजी और प्रोफेशनल कोर्स की विशेष एटीकेटी परीक्षा ओपन बुक पद्धति से शुरू हो चुकी है। विद्यार्थियों को 11 जनवरी तक अपने-अपने कॉलेजों में कॉपियां जमा करनी है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा 15 जनवरी से कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा और फरवरी में सारे रिजल्ट जारी किए जाएंगे।

एमए, एमकॉम, एमबीए और एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन चौथे सेमेस्टर, बीबीए, बीसीए छठे सेमेस्टर, पीजीडीसीए और एमजे सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों की विशेष एटीकेटी परीक्षा हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 6 जनवरी को पेपर अपलोड कर दिए हैं। पांच दिनों में जवाब लिखकर विद्यार्थियों को 11 जनवरी तक कॉपियां जमा करनी है। यहां से 13 जनवरी तक कॉपियों को मूल्यांकन केंद्र में भेजा जाएगा। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन कॉपियों की चेकिंग शुरू करेगा। इन आठ पाठ्यक्रमों में करीब साढ़े तीन हजार विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। परीक्षा विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार प्रज्जवल खरे का कहना है कॉलेजों को कॉपियां जमा करने के अलावा विद्यार्थियों के इंटरनल मार्क्स भी विश्वविद्यालय को भेजना है। उसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा।

जांचेंगे 12 हजार कॉपियां : विश्वविद्यालय ने बीए, बीकॉम और बीएससी समेत अन्य वार्षिक कोर्स की विशेष परीक्षा और सप्लीमेंट्री परीक्षा करवाई है। ढाई हजार विद्यार्थियों ने कॉपियां जमा कर दी है। मूल्यांकन केंद्र ने कॉपियां जांचना शुरू कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशेष तिवारी का कहना है यूजी ओल्ड कोर्स और पीजी कोर्स की विशेष एटीकेटी परीक्षा में लगभग सात हजार विद्यार्थी शामिल हुए हैं। फरवरी पहले सप्ताह तक 12 हजार कॉपियां जांचकर रिजल्ट घोषित करेंगे।

सात दिन में 40 पाठ्यक्रमों के रिजल्ट जारी

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नए साल के पहले सप्ताह में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 40 से ज्यादा रिजल्ट जारी किए हैं, जिनमें रिव्यू और एटीकेटी परिणामों की संख्या अधिक है। महीनों से रुके हुए रिजल्ट भी घोषित किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि 2020-21 सत्र में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को कॉलेजों में मार्कशीट दी गई। उसके आधार पर इन छात्र-छात्राओं का दाखिला सुनिश्चित किया जाएगा। कोरोना की वजह से प्रदेशभर के निजी कॉलेजों में काफी सीटें खाली हैं। इन्हें भरने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज लेवल काउंसिलिंग (सीएलसी) के आखिरी चरण को मंजूरी दी है। प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरणों में चल रही है। अधिकांश विद्यार्थी मार्कशीट और गोपनीय रिजल्ट के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। विद्यार्थियों की परेशानी को देखते हुए कुलपति डॉ. रेणु जैन ने बीते दिनों अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें रिजल्ट की स्थिति के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने एटीकेटी, रिव्यू और रुके रिजल्ट जल्द जारी करने को कहा था। सप्ताहभर में सारे परीक्षा परिणाम देने का दावा किया गया था। सूत्रों के मुताबिक अभी तक 80 फीसद रिजल्ट घोषित हुए हैं, जिसमें बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी, एमकॉम, एमए, एमएससी, एमबीए समेत अन्य पाठ्यक्रमों के विभिन्न सेमेस्टर शामिल हैं। नियमित और प्राइवेट दोनों विद्यार्थियों के रिजल्ट घोषित किए हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशेष तिवारी का कहना है कि पीजी में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज में यूजी की मार्कशीट जमा करवाना है। विद्यार्थियों को राहत देते हुए रिजल्ट तुरंत घोषित किए हैं। सात दिन में 11 हजार विद्यार्थियों के रिजल्ट जारी हुए हैं।

Badri Gautam

पीएससी से भरेंगे प्राध्यापकों के 10 हजार पद

सागर (नवदुनिया प्रतिनिधि)। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन शिक्षा के क्षेत्र में सागर के गौरव को आंच नहीं आने देगा। कॉलेजों का युक्तियुक्तकरण होगा व पीएससी के जरिये 10 हजार प्राध्यापकों के पद भरे जाएंगे, जिसमें अतिथि शिक्षकों को भी मौका मिलेगा। वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में एक करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्रशासनिक भवन एवं सेमिनार हॉल के लोकार्पण पर बोल रहे थे। वे बोले, सागर वह धरोहर है, जहां दानवीर डॉ. हरीसिंह गौर ने पूरे जिले सहित प्रदेश व देश में शिक्षा को दिशा प्रदान की है। सागर में जो केंद्रीय विवि खोला गया है, वह जल्दबाजी की देन है। इस पर विस्तार से विचार होता तो आज बुंदेलखंड के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए परेशान नहीं होना पड़ता।

Badri Gautam